

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 1115

FP/UK/ROAD/31858/2018 दिनांक: देहरादून 13 अक्टूबर 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत देवीधार-धनारी-फोल्ड मोटर मार्ग से सन्ताणगांव तक
मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 2.05 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। FP/UK/ROAD/31858/2018

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के
8बी०/यू०सी०पी०/०६/२०१४/२०१९/एफ०सी०/१४१७ दिनांक ३०.०९.२०२० द्वारा वांछित सूचना।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार की ई०डी०एस० दिनांक ३०-०९-२०२० के क्रम में चाही गयी सूचना
प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	उपरोक्त विषय पर सदंर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए प्रस्ताव पर ध्यान पूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बिन्दु सं० ०६ व ०७ के प्रतिउत्तर में यह प्रस्तुत किया गया है कि मलबा निस्तारण के लिये क्षेत्र का विवरण पैरा २.४ का और मलबा निस्तारण के लिये क्षेत्र योजना में सही किया गया है। यह पाया गया है कि मलबा निस्तारण योजना के लिये चयनित क्षेत्र आरक्षित वन भूमि में ०.१६ और गैर वन भूमि में ०.९ है० है। परन्तु पैरा बी में २.४ पर भरे गये विवरण के अनुसार वन भूमि में पूर्ण ०.२५ है० क्षेत्र शामिल उल्लेखित है। राज्य सरकार विवरण में इस विसंगति को स्पष्ट करें और इस सम्बन्ध में सही जानकारी प्रस्तुत करें।	प्रस्ताव विभाग द्वारा बिन्दु संख्या-६ एवं ७ के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि संशोधित मक डिसपोजल प्लान ऑनलाईन Additional information में अपलोड कर दिया गया है व स्पष्ट किया गया है कि याचक विभाग द्वारा १२५×२० मीटर साईज अर्थात् ०.२५ है० क्षेत्र फ० का मक डम्पिंग यार्ड आरक्षित वन भूमि में चयनित किया गया है एवं इसके अतिरिक्त दूसरा ४५×२० मीटर साईज अर्थात् ०.०९ है० क्षेत्र फ० का मक डम्पिंग यार्ड नाप भूमि में चयनित किया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम १९८० के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०जे०के० शर्मा) 15/10/20

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

ok